



अपील फार्म भरने के दिशा – निर्देश

नमस्कार मित्रों । मैं एक संस्था संचालक के रूप में आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ । फीस कमेटी ऑफिस के आधार पर कम्प्यूटर से फीस तय कर रही है जिसकी वजह से हमारी फीस बहुत कम हो रही है । जब मैंने सरकारी अधिकारियों से इसका कारण पूछा एवं जिनकी फीस तय हो कर आई है उसका विश्लेषण किया तो निम्न तकनीकी खामियों की वजह से हमारी फीस कम हुई है

1. उन्होंने हमारे खर्चों को संचालन गैर संचालन में बॉट दिया , जबकि पहले हमारे एकाउन्टिंग सिस्टम मे इस प्रकार की बात पर कोई जोर नहीं दिया जाता था, सिर्फ इस बात पर जोर होता था, कि स्कूल का पैसा किसी अन्य उपयोग मे ना लिया जाये । और अब संचालन / गैर संचालन की बात करते हैं ।
2. दूसरा उन्होंने हमारी ढूबत या छूट या छीजत को कोई महत्व नहीं दिया जबकि किसी भी व्यवसाय अथवा सेवा जिसमे पैसे का लेन देन होता है वहाँ ढूबत व छूट व छीजत होती ही है ।
3. तीसरा कर्मचारियो के वेतन का केवल अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि बीच सत्र मे यदि कोई कर्मचारी छोड़ कर चला जाता है तो संस्था को तो कई बार डबल अनुदान पर कर्मचारी रखना होता है ,कई बार अतिरिक्त क्लास लेने वाले अथवा कमजोर बच्चो को अतिरिक्त पढाई करवाने बाबत हमे अतिरिक्त टीचर्स रखने पढ़ते हैं एवं टीचर्स को अच्छी वेतन वृद्धि भी देनी होती है कई बार उनके परफोरमेंस के आधार पर । क्योंकि नियमानुसार हमसे सरकार ने हमारे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियो के बराबर वेतन देने का शपथ पत्र कई बार ले रखा है । संस्था की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं होने से पहले ही हम पूरा वेतन नहीं दे कर उन्हे अनुदान पर रखते हैं परन्तु उनकी परफोरमेंस के आधार पर हम उनके वेतन पर 10 प्रतिशत क्या कई बार डबल तक कर देते हैं ।
4. पहले संस्थाएँ चंदा लेती थी, जिसके चक्कर मे एकाउनिटिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अतः पुरानी बैलेन्स सीट के बेस पर आगे की फीस तय करना सही नहीं होगा । आपको वर्तमान फीस के लिए वर्तमान कीमत एवं खर्च देखने होगे ।
5. चौथा – मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चो की फीस का न आना – हमारी संस्थाओं मे राजस्थान भर मे यह प्रचलन है कि तीन बहिन–भाई होने से उनमे एक की फीस ली ही नहीं जाती । ऐसे बच्चो की फीस जब आती ही नहीं तो उनकी फीस का हिसाब कहाँ से देवे । फीस कमेटी ने ऐसे बच्चो की भी फीस आना माना है ।

6. आरटीई नॉमर्स 2010 के बाद आये हैं जिसके बाद सरकार ने दुनिया भर के कानून लाद दिये जिनको पूरा करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ / पूर्ण प्रशिक्षित टीचर्स एवं नई टैक्नोलोजी की व्यवस्था करनी पड़ी जिसके लिए कैपीटल इन्वेस्टमेन्ट एवं संचालन खर्चों में बढ़ौत्तरी हुई है तो फीस बढ़ना लाजमी है । लेकिन फीस कमेटी समझ रही है कि हमने आरटीई में पैसा उठाने के लिए बढ़ाई है फीस । जो गलत है
7. राज्य सरकार ने मान्यता के लिए पहले जो चार्ज कर रही थी वह राशि बहुत कम थी अब निम्न प्रकार हो गई है – तो फीस तो बढ़ानी पड़ेगी ही –
6. संस्था **एक संस्था को मान्यता में लगने वाले खर्च को देखे तो –**

यदि वर्तमान नियमों के तहत कोई भी भारतीय नागरिक अपने व्यवसाय अथवा मुनाफा कमाने के हिसाब से कोई भी कार्य करे तो उसने नियमों के तहत संबंधित विभाग में पंजीयन करना होता है जो निम्न प्रकार है एवं केवल एक बार लगता है तथा मुनाफा कमाने की पूरी छूट है । जबकि स्कूल खोलने पर कई बार कई प्रकार के शुल्क लगभग हर साल देने होते हैं – **संस्था संचालन करने वाले के लिए चैरिटी पर सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया – ऑकड़े देखे**

संस्था प्रकार	पंजीयन शुल्क	मान्यता शुल्क	कमौन्नती शुल्क माध्यमिक	कमौन्नती शुल्क उ0 माध्यमिक	बोर्ड द्वारा शुल्क एफीलियेशन फीस	परीक्षा शुल्क	कीड़ा शुल्क	सोसायटी नवीनकरण शुल्क प्रति तीन वर्ष
फर्म	1500	–	–					
कम्पनी	15000	–	–					
स्कूल	15000	55,000	3,95,000	4,20,000	4,20,000	छात्र वायज	छात्र वायज	1,000

यह तो था लगने वाला शुल्क लेकिन यदि शुल्क वृद्धि को देखे तो 2008–09 में व सत्र 2012–13 में शुल्क में सरकार ने जो वृद्धि की है वो देखिए –

सत्र	सोसायटी	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च मा0	बोर्ड
2008–09	2500	00	40,000	67,000	
2012–13	15,000	55,000	3,95,000	4,20,00	
वृद्धि प्रति0	600%	55,000%	1000%	625%	

कृप्या देखे कौन मुनाफा खोरी कर रहा है ।

उपरोक्त सभी बिन्दूओं के अतिरिक्त 2014–15 से देश मे आरटीई नियम अनिवार्य कर दिया जायेगा जिसके तहत सभी संस्थाओं को मान्यता लेने के लिए संवय का खेल का मैदान, नियमानुसार भवन, लगभग 5 एकड़ संस्थान के नाम भूमि, फर्नीचर, खेल सामग्री व अन्य सुविधाये अनिवार्य की जा रही है

7. समझ से परे है एक तरफ सुविधाएँ एवं सरकारी फीस मे बेहताशा वृद्धि की जा रही है दूसरी तरफ संस्थाओं पर फीस की कटौती की मार ।
8. एक संस्था मे निम्नांकित पद हो सकते हैं ।
हमारी संस्था मे वर्तमान मे कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या – निम्न है –
 1. प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य /उपप्रधानाध्यापक
/व्याख्याता/द्वितीय श्रेणी शिक्षक / तृतीय श्रेणी शिक्षक/ एनटीटी अध्यापक

गैर शैक्षणिक कर्मचारियों मे – व्यवस्थापक , कार्यालय स्टाफ जिसमे एक रिसेप्सन, कल्क ,लेखा कार , चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मी , डाईवर, चौकीदार, गार्ड व मैन्टीनेन्स मेनेजर आदि कार्यकरत है ।

आय – व्यय का विवरण भरते वक्त रखी जाने वाली सावधानी ध्यान से पढ़े ।

आपको सबसे पहले अपने विद्यालय की वास्तविक छात्र संख्या निकालनी है । उसके बाद उसमे से आरटीई वाले बच्चों की संख्या उसमे से घटानी है । उसके बाद जिन छात्रों को मुफ्त मे पढ़ा रहे हो उनकी संख्या घटानी है । अब बच्ची संख्या वो संख्या है जो आपको फीस देती है ।

अब इसमे से भी जिनको छूट दे रखी है उनकी संख्या निकालो तथा यदि वे पूरी फीस देते तो कितनी आती एवं आ कितनी रही है । यह राशि छूट होगी जिसे आप प्रतिशत मे दिखा सकते हो – जैसे टोटल बच्चे 200 जिसमे से मुफ्त मे 15 तो बचे 185 अब इसमे से आपने कक्षा 1 मे दो बच्चों को 100 फीस मे से 10 रु0 की छूट दे रखी है किसी को कुछ की छूट दे रखी है । तो आपको टोटल कितने पैसे का नुकसान छूट देने के कारण हो रहा है, वह संख्या एवं राशि निकालनी है ।

फिर आपके पिछले सालो छूट के अलावा कितनी राशि और आई ही नही , अर्थात बच्चे चाहे छूट वाले हो, चाहे पूरी फीस वाले यदि आपको फीस नही दे रहे हैं तो वे

झूबत वाले कहलायेगे अर्थात् जिनकी फीस गत वर्षों में नहीं आई उसी आधार पर औसत राशि झूबत निकाल लेवे ।

उदाहरण – राम नरेश स्कूल , मुरलीपुरा , जयपुर

कुल छात्र संख्या – 300

कक्षा एक से पाँचवी तक कुल बच्चे – 200

कक्षा 6 से 8 वीं तक तक कुल बच्चे 100

वार्षिक फीस एक से पाँचवी तक 2000 रु0

तथा 6 से आठवीं तक 3000 रु0

मुफ्त बच्चे एक से पाँचवी तक 15 तथा 6 से 8 वीं तक 20 टोटल 35 बच्चे मुफ्त । अब शेष बचे बच्चों की संख्या – 300 – 35 तो 265 बच्चे ।

यदि ये सारे बच्चे पूरी फीस देते तो फीस आती –

प्राथमिक कक्षाओं की फीस आती – 200–15 तो 185 गुना 2000 तो 3,70,000 रु0 आती जिसमें से 40 बच्चों को छूट की वजह से 50,000 एवं झूबत में 20,000 रु है तो एवं 6 से 8 वीं तक 100 – 20 तो 80 गुना 3000 तो 2,40,000 रु0 लेकिन 10 बच्चों को छूट की वजह से 30,000 व झूबत की वजह से 10,000 रु0 नहीं आये ।

यहाँ पुरी फीस का केलकूलेशन इस प्रकार भी किया जा सकता है ।

कुल फीस आती – 200 गुना 2000 तो 4,00,000 तथा 100 गुना 3000 तो 3,00,000 अर्थात् 7,00,000 लाख । लेकिन 35 बच्चे के मुफ्त होने से 6,10,000 ही आये ।

कुल फीस आती – 6,10,000 लेकिन उनमें से भी (**40** व 10 बच्चों को छूट होने से कुल छूट वाले बच्चे 50 हो गये एवं राशि 50,000 व 30,000 अर्थात् 80,000 हो गई जिसे प्रतिशत में निकाले तो 80,000 भाग 6,10,000 तो 13 प्रतिशत छूट हो गई) (झूबत को इस प्रकार देख सकते हैं 20,000 तथा 10,000 कुल 30,000 कितनी राशि 6,10,00 – 80,000 तो 5,30,00 पर जो 5.66 प्रतिशत के करीब होती है)

अर्थात आपको केवल 5,30,000 ही मिले 7,00,000 लाखा के स्थान पर ।

7,00,000 मे 300 बच्चो को भाग देने पर औसत प्रति बच्चा निकलता है –2333.33 रु0 जबकि 5,30,000 मे 300 को भाग देने पर 1766.66 रु0 आते है । यही फार्मूला हमारी फीस को कम करवा रहा है ।

हकीकत मे इन सब को घटाने पर जो इनकम होगी वही तो हमे मिलती है और उसी आधार पर हम खर्च करते है ।

विद्यालय की आधार भूत संरचना के सम्बन्ध मे ।

फीस के लिए पोर्टल भरते समय आधारभूत संरचना के प्रपत्रो मे निम्न तथ्यो का कॉलम नही होने से भरने से रह गये ।

आपको यह ध्यान रखना है कि – आपने जो लिखा है उसमे क्या और जोड़ना भूल गये थे उसे अब जोड सकते हो ।

1. संस्था के परिक्षेत्र

भूकि की माप मे हमने केवल खेल के मैदान की नाप लिखना भूल गये व उसका पुस्तक मुल्य नही लिखा गया । यह मैदान इस वर्ष से ही यूज मे लिया जा रहा है जिसकी कीमत अथवा किराया इसमे शामिल नही किया गया है । अर्थात किराया की राशि जोड़ी जा सकती है । किराया नामा खेल के मैदान का दिखा सकते है जरूरी नही कि ये खेल का मैदान उससे लगता हुआ हो । यह आस'पास भी हो सकता है । क्योकि पूर्व वर्षो मे यह जरूरी नही था, सो नही लिया गया एवं इसीलिए पूर्व मे इसकी लागत भी नही दिखाई गई ।

इस बार ही यूज ले रहे है । आरटीई मे यह जरूरी भी बताया गया है । या तो इसके खर्च शामिल करे अथवा आरटीई नियमो मे छूट दिलवावे ।

8. भवन का विवरण –

यहा यह ध्यान रखना है कि यदि आपके पास किराये का भवन है तो आपको किराया ही दिखाना होता है जो आपने दिखा दिया लेकिन यह ध्यान मे रखे कि अब उसमे किराया कैसे बढ़ाया जाये – यह सोचे जिसमे निम्न कार्य हो सकते है –

भवन का निर्मित क्षेत्र फल केवल पूर्ण निर्मित का ही दिखाया गया है । साथ ही आप अधिक निर्माण की बात कर सकते हैं लेकिन कमरों की संख्या हो तो ही बतावे ।

नोट – उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है जिन्होंने पोर्टल भर दिया और सारे ऑकड़े व सबूत दे दिया तो अब कैसे उनकी फीस को बढ़ाने के लिए क्या – क्या हो सकता है । यदि रखे आपने ऑकड़े स्वयं ने दिये हैं एवं उनमें हेर – फेर करना गलत होगा । हाँ जो आप लिखना भूल गये , वो ही मैं आपको याद दिला रहा हूँ । उसे इस फार्म में भर कर दे देना । पूरी केलकूलेशन के साथ । आप इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं देवे कि आपकी पुरानी बैलेन्स सीट में खर्च कम थे, हो सकता है आप उन दिनों कम लेते थे, कम सुविधा देते थे, आज पूरी सुविधा दे रहे हो तो पूरी फीस लेने का हक है ।

फिर भी कोई समझ में नहीं आये तो ग ल ती करने की बजाय 9413623033 अथवा हैल्प लाईन न0 902 416 4000 पर कॉल करे । आपसे हमारे साथी बात कर लेगे

902 – 416 – 4000 शिक्षा परिवार जयपुर

यहाँ बात नहीं होने पर भी आपके न0 कम्प्यूटर पर आ जायेगे जिस पर हम सुंविधानुसार बात कर लेगे ।